भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5479

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

तेलंगाना में सड़क अवसंरचना

5479. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना राज्य सरकार का बाहरी रिंग रोड को प्रस्तावित क्षेत्रीय रिंग रोड (आरआरआर) से जोड़ने वाले मेट्रो गलियारे के साथ-साथ दस नई ग्रीनफील्ड रेडियल सड़कों को विकसित करने का विचार है और उसने मंत्रालय से वित्तीय सहायता के रूप में 45,000 करोड़ रुपये संस्वीकृत करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके लिए कितनी निधि संस्वीकृत और व्यय की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, ग्रीनफील्ड खंडों के विकास सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य यातायात सघनता, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर किए जाते हैं।

वर्तमान में, तेलंगाना राज्य में 25,323 करोड़ रुपये की लागत की 1,423 किलोमीटर लंबाई की 52 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। सरकार ने अप्रैल, 2019 से तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर 25,000 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

सरकार ने हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्रीय रिंग रोड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उत्तरी क्षेत्रीय रिंग रोड को बाहरी रिंग रोड से जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड रेडियल सड़कों के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत राज्य की सड़कों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए तेलंगाना राज्य सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए निधि आबंटित एवं जारी भी करता है। तदनुसार, सरकार ने अप्रैल, 2019 से सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए तेलंगाना राज्य को 1,722 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

*****